बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 45 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 25 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

धर्मेंद्र ने करोड़ों लोगों का दिल जीता, वह अपने अभिनय से सदैव हमारे बीच रहेंगे : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर सोमवार को दुख जताया और कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से करोड़ों लोगों का दिल जीता तथा अपने अभिनय की बदौलत सदैव ''हमारे बीच रहेंगे। वह 89 वर्ष के थे। शाह ने 'एक्स पर पोस्ट किया, ''अपने बेहतरीन अभिनय से छह दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक थे, जिन्होंने जिस किरदार को छुआ, वह जीवंत बन उठा और अपनी इसी कला के माध्यम से उन्होंने हर आयु-वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता।

जयराम रमेश पर कार्रवाई? राज्यसभा विशेषाधिकार समिति ने की सभापति के अपमान की शिकायत पर अहम बैठक

नई दिल्ली ।

राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति, एक स्थायी संसदीय समिति, ने सोमवार को सदन के सदस्य और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ रायसभा के सभापति के खिलाफ कथित तौर पर लगातार और जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणियां करने की शिकायत पर चर्चा की। रायसभा के उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता में समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे संसदीय सौध विस्तार भवन में हुई।

एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें से एक कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के खिलाफ विशेषाधिकार संबंधी शिकायत से संबंधित था, जिसमें रायसभा के सभापति के खिलाफ कथित तौर पर लगातार और जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणियां करने और सार्वजनिक रूप से उनकी निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त करने का आरोप लगाया गया था। समिति जयराम रमेश के साक्ष्य सुनने की भी योजना बना रही है। रायसभा विशेषाधिकार समिति के अलावा, तीन अन्य समितियों की आज बाद में संसदीय सौध में बैठकें हुईं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने सभी प्रकार के मीडिया से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे प्रस्तावों और भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के विचारों को सुना। कोयला, खान एवं इस्पात समिति ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के संगठनात्मक ढांचे और प्रदर्शन - एक समीक्षा विषय पर मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य सुनने के लिए एक बैठक आयोजित की। एक अन्य पैनल, रसायन एवं उर्वरक स्थायी समिति ने देश में दवाओं की कीमतों में वृद्धि के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की भूमिका, कार्यों और कर्तव्यों की समीक्षा विषय पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत औषधि विभाग के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य सुने। रायसभा विशेषाधिकार समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के 10 सदन सदस्य शामिल होते हैं।

समिति सदन या सभापति द्वारा भेजे गए प्रत्येक विशेषाधिकार के प्रश्न की जाँच करती है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित करती है कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। यदि समिति को पता चलता है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह उल्लंघन की प्रकृति और उसके कारणों का पता लगाती है और तदनुसार सिफारिशें करती है। समिति सदन को उस प्रक्रिया की भी रिपोर्ट दे सकती है जिसका पालन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने में सदन द्वारा किया जा सकता है।

दिल्ली में जहरीली हवा,एक्यूआई 400 के पार, एनसीआर तक वायु प्रदूषण का गंभीर स्तर

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, गाजीपुर इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 441 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इस गंभीर स्तर के वायु प्रदूषण के कारण गाजीपुर सहित दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। फरीदाबाद का प्रदूषण स्तर चिंताजनक बना हुआ है। बल्लभगढ़ में अपर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जबकि एनआईटी क्षेत्र में 266 (गंभीर), सेक्टर 11 में 245 (खराब) और सेक्टर 30 में 205 एक्यूआई (मध्यम से खराब) दर्ज किया गया है। पीएम2.5 और पीएम10 मुख्य प्रदूषक हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बाहर कम समय बिताएं, मास्क पहनें और स्वास्थ्य प्रभावों से सावधान रहें। वायु गुणवत्ता सूचकांक का 401 से 500 के बीच होना गंभीर श्रेणी में गिना जाता है। इस स्तर का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, गले में खराश और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से ही श्वसन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। स्मॉग के कारण दृश्यता भी काफी कम हो जाती है, जिससे सड़क और हवाई यातायात पर भी असर पड़ने की आशंका रहती है। राजधानी में रविवार को हवा गंभीर श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गई। सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 391 दर्ज किया गया जो हवा की बेहद खराब श्रेणी है। इसमें शनिवार की तुलना में 21 सूचकांक की वृद्धि दर्ज की गई। एनसीआर में गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 437 दर्ज किया गया जो गंभीर श्रेणी है। फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही। यहां सूचकांक 237 दर्ज किया गया जो हवा की खराब श्रेणी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार, वाहन से होने वाला प्रदूषण 18.45 फीसदी रहा। इसके अलावा पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण 2.47, निर्माण गतिविधियां से होने वाला 2.72 और आवासीय इलाकों की भागीदारी 4.63 फीसदी रही।

दिल्ली प्रदूषण विरोध में माओवादी हिडमा का पोस्टर, पुलिस पर मिर्च अटैक, 15 गिरफ्तार

नई दिल्ली ।

दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण के विरोध में इंडिया गेट पर रविवार शाम को एक विरोध प्रदर्शन उस समय विवादों में घिर गया जब प्रदर्शनकारियों को शीर्ष माओवादी कमांडर मादवी हिडमा के पोस्टर दिखाते देखा गया, जो पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। हिडमा की तस्वीर और कथित तौर पर उसकी प्रशंसा में लिखे नारे अप्रत्याशित रूप से सामने आने से राजनीतिक बवाल मच गया और पुलिस ने कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित एक वीडियो में सी-हेक्सागन क्षेत्र के पास बैठे प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की ज़हरीली हवा के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाया गया है। उनमें से एक व्यक्ति भारत के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में से एक, माडवी हिडमा का स्केच वाला पोस्टर पकड़े हुए दिखाई दे रहा है, जिसके सिर पर एक करोड़ रुपये का इनाम था। भाकपा (माओवादी) की घातक बटालियन 1 का कमांडर हिडमा, बुर्कापाल घात (2017), चिंतलनार हमला (2010) और बस्तर में सुरक्षा बलों पर कई हमलों सहित कुछ सबसे भीषण नक्सली हमलों की साजिश रचने के लिए ज़िम्मेदार था। वह 18 नवंबर को अल्लूरी सीतारामराजू जिले में आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। प्रदूषण के विरोध में एक प्रदर्शन में उसके पोस्टर की मौजूदगी ने अधिकारियों को हैरान कर दिया है और राजनीतिक टिप्पणी को हवा दे दी है। दिल्ली स्वच्छ वायु समन्वय समिति द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को उजागर करना था। हालाँकि, तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने यातायात अवरुद्ध कर दिया और कथित तौर पर उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश कर रहे पुलिस अधिकारियों पर मिर्च पाउडर और काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया कि स्थिति तब हिंसक हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने हटने से इनकार कर दिया, बैरिकेड तोड़ दिए और सड़क पर बैठ गए, जिससे आपातकालीन वाहनों का आना-जाना बंद हो गया। अधिकारियों के अनुसार, तीन से चार पुलिसकर्मियों की आँखों और चेहरे पर चोटें आईं और उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। कुल 15 प्रदर्शनकारियों को ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: अफगान फ्लाइट गलत रनवे पर उतरी

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रविवार को बड़ा हादसा होने से बच गया, जब काबुल से आ रही एरियाना अफगान एयरलाइंस की एक फ्लाइट गलती से उस रनवे पर उतर गई, जहां से उसी समय एक अन्य विमान टेक ऑफ कर रहा था। एक वरिष्ठ डीजीसीए अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, घटना की जांच शुरू कर दी है। दरअसल, एरियाना अफगान एयरलाइंस की ए310 विमान, फ्लाइट एफजी 311 (काबुल से दिल्ली), को रनवे 29एल पर लैंडिंग की अनुमति दी गई थी, लेकिन विमान रनवे 29आर पर उतर गया। फ्लाइट के पायलट इन कमांड ने बताया कि 4 नॉटिकल माइल की दूरी पर उनका आईएलएस (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) सिग्नल खो गया और विमान दाईं ओर मुड़ गया, जिसके बाद कैप्टन ने विजुअल अप्रोच के आधार पर रनवे 29आर पर लैंडिंग कर दी। आईएलएस एक प्रिसिजन रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, जो विमान को रात, खराब मौसम और कम दृश्यता की स्थिति में भी रनवे तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। डीजीसीए अधिकारी ने बताया कि पायलट ने कहा कि 4 एनएम पर आईएलएस सिग्नल खो गया था और विमान दाईं ओर मुड़ा, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पुष्टि की कि एफजी 311 को रनवे 29एल पर लैंडिंग की अनुमति दी गई थी और पायलट ने भी यही पुष्टि की थी। अधिकारी के अनुसार, पायलट ने यह भी आरोप लगाया कि फाइनल अप्रोच फिक्स पार करने के बाद दोनों आईएलएस सिस्टम में खराबी आई, जबकि विमान रनवे 29एल की ओर स्थापित था। फाइनल अप्रोच फिक्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया के अंतिम चरण की शुरुआत को दर्शाता है। पायलट ने अधिकारियों को बताया कि खराब दृश्यता और आईएलएस गाइडेंस फेल होने की वजह से विमान सही अप्रोच पथ से भटक गया और दिल्ली टावर की ओर से इस दौरान किसी भी विचलन की जानकारी नहीं दी गई। लैंडिंग के बाद पायलट को एहसास हुआ कि विमान रनवे 29आर पर उतर गया है। पायलट के अनुसार, रनवे में यह विचलन आईएलएस सिस्टम फेल होने और कम दृश्यता में लेटरल गाइडेंस खोने की वजह से हुआ डीजीसीए अधिकारी ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि आईएलएस सिस्टम की समस्या विमान में थी या नहीं।

सीजेआई शपथ ग्रहण से अनुपस्थित रहने पर बीजेपी का प्रहार

नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में अनुपस्थित रहने के लिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष के नेता ने समारोह का अनादरपूर्वक बहिष्कार किया। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक परंपराओं का अनादर करने वाले अपराधी हैं और यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने महत्वपूर्ण समारोहों में भाग नहीं लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह का अनादरपूर्वक बहिष्कार करना संवैधानिक प्रक्रिया के प्रति उनकी अवमानना और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के प्रति उनके गहरे अनादर को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। जब हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का अनादर करने की बात आती है तो राहुल गांधी बार-बार अपराधी हैं और यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने महत्वपूर्ण समारोहों में भाग नहीं लिया है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता की बजाय पार्टीबाज़ी का नेता या पर्यटन का नेता कहना ज़्यादा बेहतर होगा। भारत की जनता राहुल गांधी की अहंकारी राजनीति का करारा जवाब

देगी। भाजपा के शाहनवाज़ हुसैन ने भी राहुल गांधी की आलोचना करते हुए सवाल किया कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता को अपने पद और उन प्रोटोकॉल की जानकारी है जिनका उन्हें पालन करना होता है। हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं और विपक्ष के नेता हैं। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे लोग थे जो उनसे अधिक योग्य और शिक्षित थे। शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे कई नेता हैं जो विपक्ष के नेता बन सकते थे, लेकिन राहुल गांधी अपने परिवार के नाम के आधार पर विपक्ष के नेता बने, फिर भी वह एक भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हैं। यहां तक कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तब भी राहुल गांधी गायब हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी कहाँ हैं? क्या वह पार्टी में शामिल हो रहे हैं? क्या राहुल गांधी को यह एहसास नहीं है कि वह एक संवैधानिक पद पर हैं और विपक्ष के नेता को ऐसे समारोह में उपस्थित रहना चाहिए? कांग्रेस के सदस्यों को सत्ता में रहना नहीं आता और विपक्ष की भूमिका निभाना भी नहीं आता। राहुल गांधी का आज अनुपस्थित रहना बेहद चिंता का विषय है। इसके अलावा, शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा गैर-ज़िम्मेदार व्यक्ति विपक्ष का नेता बनेगा। राहुल गांधी के पास पार्टी करने और कोलंबिया व मलेशिया घूमने के लिए खाली समय है, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह, स्वतंत्रता दिवस समारोह और भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में उनकी अनुपस्थिति गलत संदेश देती है।

प्रतीकों के सियासी टोटके फिर भी नाकाम!

उमेश चतुर्वेदी।

चुनाव नतीजों के बाद बिहार के सियासी गलियारों में एक लतीफा चल पड़ा है। मुकेश सहनी ने तालाब में कूद कर एक मछली पकड़ी, उसे बड़ी हसरत के साथ राहुल गांधी को थमाया, लेकिन राहुल के हाथ से वह मछली भी फिसल गई। जो सहनी महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, उनके हाथ सिफर ही लगा है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश के साथ राहुल गांधी और कन्हैया कुमार तालाब में कूद गए थे। 'सन ऑफ मल्लाह' के साथ दोनों का तालाब में कूदना दरअसल लोक से जुड़ने का सियासी टोटका था, लेकिन चुनाव नतीजों से साफ है कि वे सियासी टोटके एक बार फिर नाकाम रहे। राजनीति में प्रतीकों के जरिए लोकसंदेश की स्थापित परंपरा है। शिखर नेता और शीर्ष राजनैतिक परिवार लोगों से रस्मी घुलना-मिलना, उनकी सदाशयता और सादगी के प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया है। किसी हस्ती का सामान्य दिखना और आम लोगों जैसे काम करना वोटरों के समर्थन की गारंटी माना जाता रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार के राहुल जब भी ऐसा करते हैं, उनसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। यह बात और है कि राजनीति में कामयाबी पाने का यह टोटका कांग्रेस के लिए मुफीद नहीं रहा है। बिहार में बीते तीन महीनों में राहुल गांधी ने आम आदमी बनने की दो कोशिशें कीं। 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान वे एक किसान के मखाने के पानीभरे खेत में वे उतरे और बाद में चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश सहनी के साथ मछली पकड़ने के लिए गंदले तालाब में उतर गए। राहुल जब ऐसा करते हैं, बौद्धिकों का एक तबका इसे अभूतपूर्व कदम साबित करने लगता है। बहुत तो इसमें राहुल के दिल की नरमी भी खोज लाते हैं। सोनीपत में जब राहुल ने धान-रोपाई की और ट्रैक्टर चलाया, तब भी ऐसी ही उम्मीदों के पंख लग गए थे। 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दोनों चरणों में भी ऐसे कई सारे नजारे दिखे। तब एक वर्ग की नजर में राहुल की ऐसी कोशिशों से राजनीति बदलने लगी थी। लेकिन तेलंगाना छोड़, राहुल के ऐसे कदमों का कोई चुनावी फायदा नहीं मिला। इस प्रसंग में सवाल उठ सकता है कि प्रधानमंत्री भी तो ऐसे काम अक्सर करते हैं। काशी के गंगा घाट और प्रयागराज कुंभ जैसे कई मौकों और जगहों पर मोदी सफाई कर्मचारियों का पैर धो चुके हैं, उनके साथ भोजन कर चुके हैं, अयोध्या में उज्ज्वला गरीबों के घर पहुंच नेह जताते रहे, किसी परियोजना के पूरा होने के बाद श्रमदान दे चुके मजदूरों संग खाना खाते रहे हैं। तो उन पर ऐसे सवाल क्यों नहीं उठते। ऐसा नहीं कि सवाल नहीं उठते। वैचारिक खांचे में बंटी राजनीति और समाज में महज विरोध के लिए सवाल उठते रहे हैं। जिनका जवाब बीजेपी की बजाय वोटर देते रहे हैं। सवाल है कि राहुल के लोक लुभावन कदमों के बावजूद लोग कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? कुछ महीने पहले कांग्रेस के अंदरूनी हलके में वरिष्ठ नेताओं से पार्टी को उबारने को लेकर राय मांगी गई थी। तब कुछ नेताओं ने अपने भविष्य प्रबुद्ध लोगों की राय मांगी थी। ये पता नहीं कि नेताओं ने पार्टी को सफलता के गुर सुझाए या नहीं। वैसे कांग्रेस के जैसे अंदरूनी हालात हैं, शायद ही कोई नेता सही और वाजिब राय देने का साहस जुटा पाए। सियासी नाकामी से उबरने का नुस्खा वरिष्ठ कांग्रेसियों के पास भी है। चूंकि यह नुस्खा बेहद कड़वा है। डर ये है कि कड़वी दवा सुझाना कठिन हो सकता है। लिहाजा राय देने से लोग बच रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन की प्रतिनिधि पार्टी रही कांग्रेस अखिल भारतीय संगठन से लैस रही है। सत्तावादी राजनीति के दौर में कांग्रेस इस थाती पर गर्व कर सकती है। लेकिन संगठन को गतिशील बनाने वाले सही मुद्दों और लोकमर्म को छूने वाले विचारों से वह सर्वथा दूर है। राहुल उन्हीं मुद्दों को ज्यादा उछालते हैं, जिन्हें उनके वामपंथी सलाहकार सुझाते हैं। बौद्धिक और अकादमिक जगत इससे चाहे जितना भी आकर्षित हो, जमीनी स्तर पर वह अस्वीकार्य हो चुका है। निजीकरण की कुछ खामियां हैं, लेकिन भूलना नहीं होगा कि निजीकरण ने चमक-दमक भी बढ़ाई है। भले ही एक वर्ग तक निजीकरण की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। उस वर्ग का भी सपना चमक को हासिल करना है। वामपंथी वैचारिकी इसे नहीं समझती। वह जाहिर करती रही है कि अतीत की तरह अब भी समूचा देश अंधेरे में डूबा है। वह भूल जाती है कि देश पर सबसे ज्यादा दिनों तक कांग्रेस का ही शासन रहा है। जातिवाद कड़वी सच्चाई है। हजारों साल की परंपरा का एकदम खत्म होना संभव नहीं। कड़वा सच है कि जातिवाद को दूर करने और उससे दूर रहने का दावा करने वाली राजनीति और बौद्धिक भी इससे अछूते नहीं। उनके अंदरूनी खांचे में जातिवाद कई रूपों में मौजूद है। वैसे जाति और धर्म के संदर्भ में समूचे देश और समाज को एक फॉर्मूले से समझना संभव नहीं। कांग्रेस यही गलती दोहरा रही है। राहुल के सलाहकारों की टीम उन्हें इसी फॉर्मूले पर बार-बार आगे बढ़ने का सुझाव देती है। अब तो योगेंद्र यादव भी राहुल गांधी के बड़े सलाहकार हैं। समाजवादी दिग्गज किशन पटनायक के शिष्य यादव की सोच पर समाजवाद का कम, वामपंथ का असर ज्यादा है। 1999 में एक्जिट पोल को काला जादू न मानने वाले योगेंद्र को अब बीजेपी की हर जीत में शंका ही नजर आती है। कांग्रेस आलाकमान के तमाम सलाहकार कभी शिक्षा के लालगढ़ की राजनीति के प्रतीक रहे। दुर्भाग्यवश उनकी सामाजिक सोच जमीनी हकीकत की बजाय वामपंथी दर्शन से ज्यादा प्रभावित है। इस टीम के अनुसार ऊंच-नीच और जात-पात का विचार समूचे देश में एक जैसा है। लेकिन यह अधूरा सच है। समूचा देश न तो एक तरह से सोचता है न ही उसका एक-सा व्यवहार है। शीर्ष नेतृत्व की सलाहकार मंडली अलग-अलग हिस्सों की माटी के रंग, व्यवहार और विचार से कोसों दूर है। राहुल को इन दिनों अपनी दादी इंदिरा गांधी की याद खूब आती है। लेकिन वे इंदिरा के कई गुणों को अब तक समझ नहीं पाए हैं..। समाज को लेकर इंदिरा की समझ गहरी थी। यही वजह है कि वक्त और इलाके की परंपरा के मुताबिक, किसी इलाके में ठेठ बहू बन जाती थीं, तो किसी इलाके में आधुनिक महिला। कुछ इलाकों में वे अपने सिर पल्लू रखती थीं तो कुछ इलाकों में नहीं। आज इंदिरा रहतीं और वैसा करतीं तो शायद कांग्रेस के मौजूदा सिपहसालारों की नजर में वे दकियानूस मान ली जातीं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस की छतरी तले कई विचारधाराएं काम कर रही थीं। इंदिरा काल के किंचित वामपंथीकरण को छोड़ दें तो पार्टी का नजरिया ज्यादातर मध्यमार्गी और समाजवादी ही रहा। इंदिरा काल में वामपंथी प्रभाव इतना नहीं रहा कि वह अपनी बुनियादी विचारधारा को ही बदल दे। लेकिन आज देश की सबसे पुरानी पार्टी पर वामपंथ का खूब असर है। इसलिए उसके मुद्दे भी इसी से प्रभावित हैं। वाम वैचारिकी हर मुद्दे को नैरेटिव विशेष के लिहाज से उछालती है। सांप्रदायिकता,धर्म और जाति से जुड़े उसके विचार पारंपरिक से इतर हैं। बीजेपी के खिलाफ हर बार सांप्रदायिकता का वामपंथी एजेंडा और नैरेटिव का उठना इसी मंडली की करामात होती है। इस नजरिया वाली सांप्रदायिकता का प्रतिकार सूत्र बीजेपी ने खोज लिया है। उसके लिए यह पिच आसान हो गई है। इसीलिए वह ज्यादातर चुनावों में कांग्रेस को मात दे रही है। इसी सोच के चलते कांग्रेस यूपी, बिहार जैसे राज्यों में उन दलों के छोटे भाई की भूमिका तक सीमित रह गई है, जिनका उदय गैरकांग्रेसवाद की बुनियाद पर हुआ है। सवाल और सूचना से लैस लोग इन प्रतीकों के छुपे संदेशों को समझने-बूझने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस इस प्रक्रिया को नहीं समझ पा रही। बिहार में कांग्रेस का बड़ा दांव नहीं रहा। 243 सीटों वाली विधानसभा में वह महज 61 सीटों पर मैदान में रही। मछली पकड़ने और तालाब में छपाक करने का राहुल दांव नाकाम रहा।

सम्पादकीय...

चुनाव आयोग पर उठते सवाल

भारत के चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक सन्देहों से परे रही है परन्तु हालिया वर्षों के दौरान इसकी साख वह नहीं रही है जिसके लिए यह विश्व के लोकतान्त्रिक देशों में जाना जाता था। पूरे विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला भारत ऐसा देश है जिसमें सरकारों का गठन नागरिकों द्वारा मतदान करा कर किया जाता है। भारत में मतदाताओं की संख्या ही लगभग 98 करोड़ के आसपास है जो कि दुनिया के अधिसंख्य देशों की आबादी के मुकाबले बहुत बड़ी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या के मतदाता समूह को नियमबद्ध करना कोई मामूली काम नहीं है। इसीलिए लोकतान्त्रिक दुनिया के अग्रणी देश तक भारत की चुनाव प्रणाली का अध्ययन करने आते रहे हैं। भारत की चुनाव प्रणाली की खूबी यह है कि इसमें देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म या जाति अथवा वर्ग या सम्प्रदाय कोई भी हो। यह वोट का अधिकार कोई छोटा अधिकार नहीं है क्योंकि इसी के माध्यम से भारत के हर नागरिक को गांधी बाबा स्वयंभू बना कर गये हैं। लोकतन्त्र में इस वोट की कोई भी कीमत नहीं आंकी जा सकती है। चुनाव आयोग का असल काम यही है कि वह लोगों को अपने इस अधिकार को अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करे जिससे किसी भी बनने वाली सरकार में लोगों की इच्छा का समावेश हो सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतन्त्र व स्वायत्त चुनाव आयोग का गठन इसीलिए किया था कि देश की राजनीतिक प्रणाली में सत्ता पर काबिज कोई भी दल किसी भी सूरत में अपनी इच्छा न थोप सके। इसके लिए चुनाव प्रणाली को इतना पाक-साफ बनाया गया कि चुनावों के अवसर पर प्रशासन की बागडोर भी चुनाव आयोग को सौंपने का निर्णय किया गया। मगर चुनाव आयोग का यह भी कर्तव्य बनता है कि वह भारत की बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप बढ़ते वयस्क नागरिकों को मतदाता बनाये। इस क्रम में चुनाव आयोग हर साल मतदाता सूचियों का संशोधन करता है परन्तु इस बार बिहार के चुनावों से पहले आयोग ने सूचियों का गहन पुनरीक्षण करने का फैसला किया जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई। देश की सबसे बड़ी अदालत यह तय करेगी कि क्या गहन पुनरीक्षण कराना संवैधानिक है? इस मामले में न्यायालय में बहस जारी थी कि इसी दौरान बिहार के चुनाव हो गये और उनके बाद आयोग ने देश के 12 राज्यों में गहन पुनरीक्षण कराने के आदेश जारी कर दिये। आजकल यह कार्य इन सभी प्रदेशों में जोर-शोर से चल रहा है। इन 12 राज्यों में तीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्र भी शामिल हैं। गहन पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवाएं लेकर ही करता है जिनमें सरकारी स्कूलों के अध्यापक सर्वाधिक होते हैं। ये कर्मचारी ब्लाक स्तर पर मतदाता सूचियों की जांच करते है और मतदाताओं के नाम की तसदीक करते हैं। इन्हें अंग्रेजी में बीएलओ कहा जाता है। जिन 12 राज्यों में पुनरीक्षण का काम चल रहा है वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई बीएलओ काम का भारी दबाव होने की वजह से आत्महत्या तक कर रहे हैं। यदि मीडिया की खबरों को सही मानें तो अभी तक पांच राज्यों प. बंगाल, केरल, गुजरात मध्य प्रदेश व राजस्थान में 14 बीएलओ खुदकशी कर चुके हैं। यह बहुत गंभीर मामला है जिस तरफ चुनाव आयोग के साथ ही राज्यों की सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए और बीएलओ पर डाली गई जिम्मेदारियों की समीक्षा करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया है कि आगामी 4 दिसम्बर तक पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि 4 दिसम्बर तक अपने क्षेत्र के हर वयस्क मतदाता का हिसाब-किताब बीएलओ को अन्तिम रूप से करना होगा। सुनने में यह काम जितना सरल लगता है करने में उतना ही मुश्किल है क्योंकि बीएलओ को ही आम जनता के इस बारे में उठाये गये हर सवाल का जवाब देना पड़ता है।बीएलओ अधिकतर शिक्षक वर्ग के होते हैं और उन पर यह जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तौर पर उनके द्वारा किया गया पुनरीक्षण पूरी तरह शुद्ध हो। इस प्रक्रिया में उन्हें सभी मतदाताओं की गहरी तसदीक करनी पड़ती है। प. बंगाल के नदिया जिले में 53 वर्ष की एक बीएलओ ने काम के बोझ की वजह से ही आत्महत्या की। उनके परिवार के सदस्यों की मानें तो उन पर काम का बोझ इतना अधिक था कि वह अपना मानसिक नियन्त्रण नहीं रख पाई। इसी प्रकार गुजरात के तापी जिले में एक बीएलओ की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु पिछले गुरुवार को हो गई। राज्य में इससे पूर्व भी दो और बीएलओ इसी तरह अपनी जान गंवा बैठे। मध्य प्रदेश में पिछले सप्ताह दो बीएलओ मौत का ग्रास बन गये। इनके परिवारजनों ने भी काम का अधिक बोझ होने की शिकायत की। चुनाव आयोग का यह कर्तव्य बनता है कि वह इन सभी बीएलओ की मृत्यु का असली कारण जाने और समझे कि क्या काम का बोझ ही उनकी आत्महत्या का सबब बन रहा है। आयोग ने प. बंगाल के बीएलओ की आत्महत्या पर तो रिपोर्ट मांगी है मगर अन्य राज्यों में हुई ऐसी घटनाओं का अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग इस बारे में उच्च स्तरीय फैसला ले और बीएलओ के साथ कुछ अन्य कर्मचारी भी लगाये।

कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत

बिहार चुनाव में भीषण पराजय के बाद कांग्रेस की यही हालत हो गई है। चुनावी जीत के लिए भ्रष्टाचार और जंगलराज से समझौता करने वाली कांग्रेस हार की खीझ चुनाव आयोग पर निकाल रही है। यह पहला मौका नहीं है कि जब कांग्रेस ने अपनी गिरेबां में झांकने के बजाए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कांग्रेस की इस हरकत के लिए देश के प्रबुद्ध जनों ने फटकारा है। देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक पत्र लिखकर राहुल गांधी की आलोचना की है। यह पत्र लिखने वालों में 16 जज, 123 रिटायर नौकरशाह (जिनमें 14 राजदूत शामिल हैं) और 133 रिटायर सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं। सभी ने एक खुला पत्र लिखकर विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की है। इस पत्र में लिखा है कि हम, नागरिक समाज के वरिष्ठ नागरिक इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर बल प्रयोग से नहीं, बल्कि इसकी आधारभूत संस्थाओं के विरुद्ध जहरीली बयानबाजी की बढ़ती लहर से हमला हो रहा है।

कुछ राजनीतिक नेता, वास्तविक नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करने के बजाय, अपनी नाटकीय राजनीतिक रणनीति के तहत भड़काऊ लेकिन निराधार आरोपों का सहारा ले रहे हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बार-बार चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा है कि उनके पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है और उन्होंने दावा किया कि उनके पास 100 प्रतिशत सबूत हैं। अविश्वसनीय रूप से असभ्य बयानबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जो मिला है वह एक परमाणु बम है और जब वह फटेगा, तो चुनाव आयोग के पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। राहुल गांधी ने यह भी धमकी दी है कि चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस काम में शामिल है, वह उन्हें नहीं बख्शेंगे।

उनके अनुसार, चुनाव आयोग देशद्रोह कर रहा है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने (राहुल गांधी) सार्वजनिक रूप से धमकी दी है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त रिटायर हुए, तो वह उन्हें परेशान करेंगे। फिर भी, इतने तीखे आरोपों के बावजूद उन्होंने निराधार आरोप लगाने और लोक सेवकों को उनके कर्तव्य पालन के दौरान धमकाने की अपनी जवाबदेही से बचने के लिए निर्धारित शपथ पत्र के साथ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की है। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता और वामपंथी एसआईआर के खिलाफ इसी तरह की तीखी बयानबाजी में शामिल हो गए हैं, यहां तक कि यह भी घोषित कर दिया है कि आयोग भाजपा की बी-टीम की तरह काम करके पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों को आमंत्रित करके उनके साथ बैठक करने की कई बार कवायद की है ताकि उनकी समस्याओं और मदों का निदान कर सकें। आयोग ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया लेकिन वे आयोग के दफ्तर नहीं गए। चुनाव आयोग ने जनता दल (सेक्युलर) के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी बातें सुनीं और सुझाव लिए। आयोग ने अब तक पांच राष्ट्रीय पार्टियों और 16 राज्य पार्टियों के साथ बैठकें की हैं। कांग्रेस एक मात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसने अभी तक चुनाव आयोग के साथ बैठक नहीं की है। राहुल गांधी ने पहले कर्नाटक में वोटरों के पंजीकरण में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और बिहार में वोट चोरी का दावा करते हुए वोटर अधिकार यात्रा निकाली। आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुधार किए हैं, जैसे ईवीएम माइक्रो-कंट्रोलर की जांच और वीवीपैट पर्चों की गिनती अनिवार्य करना। आयोग ने 334 निष्क्रिय पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा दिया है और 476 अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आयोग ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 3 लाख डुप्लिकेट वोटर कार्ड नंबर भी रद्द किए हैं। आयोग ने अब तक पांच राष्ट्रीय पार्टियों और 16 राज्य पार्टियों के साथ मीटिंग की है। इन मीटिंग में आयोग सबसे सुझाव लेता है कि चुनाव को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आयोग के साथ कोई मीटिंग नहीं की है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 15 मई को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन कांग्रेस ने उस दिन मीटिंग करने से मना कर दिया। कांग्रेस ने अभी तक आयोग को कोई नई तारीख नहीं बताई है कि वे कब मीटिंग कर सकते हैं। राहुल गांधी ने एक अखबार में लिखे गए लेख में कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में गलत नाम जोड़े गए और सवाल उठाया था कि शाम 5 बजे के बाद वोटिंग अचानक बढ़ गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने 12 जून को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वे आएं और अपनी चिंताओं के बारे में सीधे बात करें। लेकिन राहुल गांधी ने आयोग की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। विपक्षी दलों के नेताओं और कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देशों के साथ इस पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसीआई) से आग्रह किया कि वह आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाताओं की पहचान साबित करने के लिए आधार, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी कार्ड) को स्वीकार्य दस्तावेजों के रूप में अनुमति देने पर विचार करे। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग से कहा कि यदि वह मतदाताओं द्वारा अपनी पहचान साबित करने के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में आधार, राशन कार्ड और ईपीआईसी को शामिल नहीं करने का निर्णय लेता है, तो वह इस पर स्पष्टीकरण दे। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद, चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए दस्तावेजों की सूची में 11 दस्तावेज शामिल हैं और यह संपूर्ण नहीं है। इसलिए, हमारी राय में, यह न्याय के हित में होगा यदि आधार कार्ड, ईपीआईसी कार्ड और राशन कार्ड को भी इसमें शामिल किया जाए। यह चुनाव आयोग पर निर्भर है कि वह दस्तावेज लेना चाहता है या नहीं। यदि वह दस्तावेज नहीं लेता है, तो उसे इसके लिए कारण बताना होगा और इससे याचिकाकर्ताओं को संतुष्ट होना होगा। विपक्षी दलों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि एसआईआर को जानबूझकर टारगेट वर्गों (मुस्लिम, दलित, आदिवासी) के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए एक साजिश के रूप में डिजाइन किया गया है। विपक्ष इसे वोट चोरी बता रहा है। एसआईआर के विरोध की असली वजह बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं। ये कांग्रेस और विपक्षी दलों के वोट बैंक हैं, हालांकि बिहार में मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस के बजाए असुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर ज्यादा भरोसा किया। कांग्रेस और विपक्षी दलों को न चुनाव आयोग पर भरोसा है और न ही सुप्रीम कोर्ट पर, यदि ऐसा होता तो आयोग की कार्रवाई में हिस्सा लेने से पीछे नहीं हटते। यह निश्चित है कि हार का दोष चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने से कांग्रेस भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण, जातिवाद और मुस्लिम तुष्टिकरण जैसे चुनावी हार के कारणों से मुंह नहीं मोड़ सकती। कांग्रेस के लिए अब देश के मतदाताओं को इन मुद्दों पर बरगलाना आसान नहीं है। कांग्रेस के लिए बेहतर है कि पुरानी गलतियों से सबक सीखे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचे, तभी कांग्रेस मतदाताओं में खोया हुआ विश्वास फिर से हासिल कर पाएगी।

सेना बनाम सर्वोच्च न्यायालय बनाम मानवाधिकार

पिछले दिनों एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इस पोस्ट में सेवानिवृत्त कर्नल एएस. राय का बयान सेना के उस वर्ग की भावना को स्पष्ट करता है जो लगातार आतंकवाद, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता वाले इलाकों में डटा रहता है। जब सैनिक सीमाओं या कश्मीर जैसे 'संवेदनशील क्षेत्रों' में आतंकवाद का सामना करते हैं तब उन्हें कुछ फैसले अक्सर सैकंडों में लेने पड़ते हैं। इसमें औपचारिकताओं के लिए समय नहीं होता। जो भी निर्णय लेना होता है वह उन सैनिकों को दिए गए प्रशिक्षण और अपने विवेक से ही लेना पड़ता है। इस पोस्ट ने सीधे सवाल उठाया, क्या आपने कभी अपने बेटे को खोया है? -यह व्यवस्था से उपजी पीड़ा और असंतोष की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इसका मूल भाव यही है कि जब सैनिक आतंकवादी का सामना करता है तो वह कानून या न्यायालय की व्याख्याओं से अधिक अपने प्रशिक्षण और परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। बाद में उस पर अभियोग या अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगना उसे अपमानजनक महसूस होता है। दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि संविधान की मूल भावना, 'हर नागरिक के मौलिक अधिकार' से निर्देशित होती है। न्यायालय किसी सेना या व्यक्ति का विरोध नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि 'राज्य की शक्ति' जवाबदेही से परे न हो। कश्मीर या किसी अशांत क्षेत्र में नागरिकों पर अत्याचार या फर्जी मुठभेड़ों के आरोप अक्सर सामने आते हैं। यदि जांच का हक छीन लिया जाए तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे। न्यायालय यह नहीं कहता कि आतंकवादी को बचाया जाए, बल्कि यह मांगता है कि निर्दोष लोग आतंकवादी समझकर मारे न जाएं। यही 'न्याय का नैतिक आधार' है। पोस्ट में आतंकवादियों के मानवाधिकारों को लेकर जो कटाक्ष किया गया है, वह भावनात्मक प्रतिक्रिया है लेकिन मानवाधिकारों का सार आतंकवादी के प्रति करुणा नहीं, बल्कि बिना भेदभाव सिद्धांतों पर आधारित न्याय को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है। जब किसी संदिग्ध की मौत की जांच होती है तो लक्ष्य अपराधियों को बचाना नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकना होता है। वैश्विक संदर्भ में भी अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस जैसे देशों में वॉर क्राइम्स या एक्सेसिव फोर्स पर सवाल उठते रहे हैं। सशक्त लोकतंत्र वे है जो अपने संस्थानों से प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं। यह साफ है कि सेना को अपराधी न मानें और न्यायपालिका को देश विरोधी न कहें। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक निष्ठा के दो मजबूत स्तंभ हैं। समस्या तब आती है जब संवैधानिक प्रक्रिया को देश विरोधी मानसिकता या सैनिक कार्रवाई को न्याय की हत्या मान लिया जाता है। इससे संवाद में विघटन और अविश्वास बढ़ता है। समुचित समाधान यही है कि सेना को 'ऑपरेशनल प्रोटेक्शन' मिले, ताकि तत्काल कार्रवाई में की गई गलती अपराध न माना जाए लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करने पर न्यायिक जांच की प्रक्रिया बनी रहे। ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पर राष्ट्रभक्ति की भावना को सीधा स्पर्श करते हैं। खतरा इस बात में है कि भावनाओं की लहरों में तथ्य और कानूनी सीमाओं की अनदेखी होने लगती है। न्यायपालिका, सेना और मानवाधिकार, ये विरोधी नहीं बल्कि लोकतंत्र के पूरक अंग हैं। सोशल मीडिया पर एकांगी नैरेटिव अंततः सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है। भारत में सेना, सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार को लेकर टकराव की घटनाएं केवल हाल ही की नहीं, बल्कि देश के इतिहास में समय-समय पर सामने आई हैं। 18वीं शताब्दी में कोलोनियल शासन के दौरान सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच अधिकार को लेकर पहली बड़ी भिड़ंत कोसिजुरा मामला में देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सेना का इस्तेमाल करते हुए अपनी शक्तियां बढ़ाने का प्रयास किया, जबकि गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने अदालत के आदेशों को चुनौती दी और सेना को अदालत के खिलाफ तैनात कर दिया। यह विवाद बंगाल यूडिकेचर एक्ट 1781 के पास होने तक चलता रहा, जिसने अदालत की सीमाएं तय कर दीं और टकराव का अंत किया। इस मामले ने जता दिया कि अधिकारों की अस्पष्टता शक्ति संघर्ष का हमेशा केंद्र रही है। 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर देशद्रोह और हत्या के आरोप लगे और उन पर कोर्ट मार्शल चलाया गया। ब्रिटिश सरकार ने इन सैनिकों की गतिविधियों को किंग के खिलाफ युद्ध माना, जबकि भारतीय जनता और नेताओं ने देशभक्ति की भावना को कानूनी प्रक्रिया के विरोध में जोरदार तरीके से रखा। इस संघर्ष में अदालत के आदेशों और जनता के मानस के बीच गहरा विभाजन आया। नगा पीपल्स मूवमेंट बनाम भारत सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय में एएफएसपीए की वैधता को चुनौती दी गई लेकिन अदालत ने यह माना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेना को अतिरिक्त अधिकार देने का प्रावधान संविधान के खिलाफ नहीं। फिर भी अदालत ने सेना के अधिकारों पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश जारी किए। इस मामले में मानवाधिकार और सैन्य अधिकार की सीमा को लेकर बड़ी बहस छिड़ी। 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान सर्वोच्च न्यायालय से सेना/पैरामिलिट्री तैनात करने की मांग की गई थी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे आदेश देना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह कार्य कार्यपालिका का दायित्व है। बावजूद इसके, कभी-कभी अदालत ने सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए हैं, जैसे 2008 के ओडिशा के दंगों या 2023 के पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में भी कभी-कभी सेना और मानवाधिकार संस्थाओं के बीच टकराव सामने आते हैं। मगर वहां बार-बार यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनहित और राज्य हित के बीच संतुलन बना रहे। मणिपुर अथवा कश्मीर में जारी घटनाओं में अदालत के आदेश, सेना के अधिकार और जनता का विश्वास तीनों पहलू परस्पर टकरा सकते हैं। मगर, लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें संतुलन बनाना और संवाद की प्रक्रिया में सही समाधान ढूंढना ही होना चाहिए। जरूरत इसी बात की है कि अतीत के अनुभवों से सीखकर आज के तात्कालिक विवादों को अंधी भावनाओं के बजाय गहन विश्लेषण और खुले संवाद द्वारा हल किया जाए। संविधान की साझा जिम्मेदारी मानते हुए सुरक्षा और अधिकार दोनों के बीच संतुलन जरूरी है।

समावेशी कार्यबल के लिए श्रम संहिता सुधार

भारत एक ऐतिहासिक युग की शुरुआत में खड़ा है, यह राष्ट्रीय आत्मविश्वास का क्षण है, क्योंकि देश श्रम संहिताओं को लागू कर रहा है, जिन्हें व्यापक रूप से आजादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े और दूरदर्शी सुधारों में माना जाता है। इन संहिताओं के लागू होने से पुराने, जटिल और औपनिवेशिक दौर के श्रम कानूनों की जगह एक आधुनिक और सरल श्रम व्यवस्था ले रही है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दिशा में देश के लक्ष्यों के अनुरूप है। ये सुधार श्रमिकों को अधिक सुरक्षा, सुविधाएं और अधिकार देते हैं, और साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत बनाते हैं, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं और वंचित वर्ग काम करते हैं। सुरक्षा से सशक्तिकरण तक श्रम संहिताएं एक ऐसे नए दौर की शुरुआत करती हैं, जहां श्रमिकों विशेषकर महिलाओं को गरिमा, न्याय और जरूरी सुरक्षा की व्यापक पहुंच देकर उन्हें सच में सशक्त किया जा रहा है। वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता यह तय करती हैं कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिले, और हर श्रमिक तक सामाजिक सुरक्षा पहुंच सके। इससे ऐसा वातावरण बनता है जो महिलाओं की सुरक्षित और पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के कवरेज के विस्तार से स्वास्थ्य, मातृत्व और आय सुरक्षा और मजबूत होती है। इसका लाभ ग्रामीण इकाइयों से लेकर बड़े एमएसएमई क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं तक सभी को मिलता है। परिवार की परिभाषा को बढ़ाकर उसमें अब महिला के ससुर-सास को भी शामिल किया गया है। यह बदलाव इस बात को समझता है कि परिवार की देखभाल की जिम्मेदारियां महिलाओं पर अधिक होती हैं, और इसलिए ऐसा प्रावधान महिलाओं के रोजगार में भाग लेने के लिए एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार करता है। इन सभी प्रावधानों को मिलाकर देखा जाए तो यह एक नए सामाजिक अनुबंध का निर्माण करते हैं, जिसमें भारत की बदलती श्रम व्यवस्था के केंद्र में महिलाओं को रखा गया है। स्वास्थ्यप्रद और सुरक्षित कार्यस्थल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन्स कोड भारत में कार्यस्थलों पर कल्याण और सुरक्षा के लिए एक आधुनिक मानक तैयार करता है। इसमें क्रेच, शौचालय, पीने का पानी, कैंटीन और आराम करने की जगह जैसी सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं, ताकि एमएसएमई कार्यस्थल सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्पादकता बढ़ाने वाले बन सकें। मानक कार्य घंटों का निर्धारण, उपयुक्त परिस्थितियों में वर्क-फ्रॉम-होम जैसी लचीली व्यवस्थाएं, और 180 दिन पूरे होने पर पेड लीव का अधिकार। ये सभी प्रावधान काम और निजी जीवन में बेहतर संतुलन बनाते हैं। इससे भारत की श्रम व्यवस्था आधुनिक अपेक्षाओं और श्रमिक कल्याण के वैश्विक मानकों के अनुरूप होती जा रही है। 40 वर्ष और उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए हर साल मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है। इससे बीमारियों को पहले ही पहचानने, रोकथाम पर ध्यान देने और लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शाही ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साथ पॉकेटवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शाही, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/...)

भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों का मोदी और योगी सरकार कर रही विकास : केशव मौर्या

कसया, कुशीनगर।

भगवान बुद्ध के दर्शन कर जीवन सार्थक हुआ। मोदी जी के निर्देश पर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेष को लेकर रूस जाने का अवसर मिला। उक्त बातें प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कुशीनगर में मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन पूजन के पश्चात कही। कहा कि रूस में बड़ी संख्या में लोग भगवान बुद्ध के अवशेष को दर्शन करने को आए। भगवान बुद्ध से जुड़े सबसे अधिक स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी इन पवित्र स्थलों का विकास कर रहे हैं। एक सवाल जिसमें सपा नेता रविदास मल्होत्रा के आरोप पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सपाई मिडिया में आने के लिए इस तरह की बात बोलते हैं। सपा के तमाम बड़बोले नेता हैं। सपा रामद्रोही पार्टी है। सपाइयों के बोलने का जवाब जनता देती है। अभी बिहार में जनता ने जवाब दिया है। बंगाल और यूपी में भी जनता जवाब देगी। घुसपैठियों का कोई भारतीय स्वागत नहीं करेगा। राम लला के जन्मभूमि पर भव्य प्रभु श्रीराम का मंदिर बना है। प्रधानमंत्री मोदी कल

धर्म ध्वजा फहराने वाले हैं। पांच सौ साल पहले आक्रमणकारी ने राममंदिर को तोड़कर ढांचा खड़ा किया था। उस ढांचे को रामभक्तों ने धराशाई किया। रामभक्तों ने राममंदिर बनाने के संकल्प लिया था जो पूरा हो गया है।

श्रीराम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। विदेशी आक्रांताओं ने कई मंदिरों को तोड़ा। सोमनाथ का मंदिर भी तोड़ा लेकिन सरदार पटेल ने उसे बनवाया। सरदार पटेल अगर पहले प्रधानमंत्री होते तो अयोध्या मथुरा और काशी की समस्या समाप्त हो गई होती। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा नहीं होता। भ्रष्टाचार नहीं होता, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होती, परिवार वाद और भ्रष्टाचार जन्म नहीं लेता। हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई के लिए कानून बना है। भारत आने पर स्वागत होगा नागरिकता भी मिलेगी। कोई मुस्लिम घुसपैठिया आकर गरीबों का हक मरेगा। सपा बसपा कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों को सत्ता में बैठा रहा है तो यह अब नहीं होगा।

चुनाव आयोग भी एसआईआर चलाकर पवित्र महायज्ञ कर रहा है इससे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा। बूथ को लूटकर कोई सत्ता नहीं प्राप्त कर पाएगा। सिंध की संस्कृति हमारे देश से मिलती है।सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं।

उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या और प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बुद्ध का किया दर्शन, चढ़ाया चीवर

कसया, कुशीनगर।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सोमवार को कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचे जहां जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका बुके देकर स्वागत किया। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री श्री मौर्या और प्रभारी मंत्री श्री सिंह बुद्ध स्थली कुशीनगर पहुंचे और मुख्य महा परिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा प्रतिमा का दर्शन, पूजन कर चीवर चढ़ाया। कुशीनगर के महत्व और विकास को लेकर अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से वार्ता की। इसके बाद वह बर्मी मंदिर में जाकर भिक्षु संघ के अध्यक्ष रहे दिवंगत भदंत ज्ञानेश्वर की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात वह थाई मंदिर पहुंचे जहां भंते डॉ पी सोम पोंग के निर्देशन में धम्म पाठ के बीच विशेष पूजन अर्चन किया। यहां प्रमुख भिक्षु डॉ सोम पोंग ने बुद्ध की प्रतिमा देकर उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री का किया। इससे पूर्व एयरपोर्ट पर सांसद विजय कुमार दूबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, विधायक पीएन पाठक, विधायक

भिक्षु संघ के अध्यक्ष दिवंगत भदंत ज्ञानेश्वर को दी श्रद्धांजलि

मोहन वर्मा, विधायक विवेकानंद पांडेय, विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, विधायक मनीष जायसवाल, विधायक डॉ असीम राय, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री राजेश्वर सिंह, नपा अध्यक्ष कुशीनगर किरन जायसवाल, अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जयसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल आदि नेताओं ने बुके देकर स्वागत किया। इसी क्रम में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, एसपी केशव कुमार, उपजिलाधिकारी डॉ संतराज सिंह बघेल आदि ने भी स्वागत किया। इस दौरान भंते महेंद्र, भंते अशोक, भंते उपाली, मंडल अध्यक्ष आद्या पांडेय, किरन सिंह, गोपाल जी राय, बालिस्टर भारती, शैलेन्द्र सिंह, पुनीत पांडेय, अंबिकेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश कुशवाहा, विवेक गोंड, सूरज यादव, गौतम शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की व्यापक समीक्षा

एसआईआर, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याओं व योजनाओं पर सख्त निर्देश

कुशीनगर ।

कलेक्ट्रेट सभागार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में आज जनपद के विकास कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सांसद, विधायक तथा सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने एसआईआर कार्यों पर विशेष जोर देते हुए स्पष्ट कहा कि कोई पात्र नागरिक छूटे नहीं, कोई घुसपैठिया शामिल न हो। नए व युवा मतदाताओं के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएलओ व बूथ स्तर कर्मियों से सम्मानजनक व्यवहार और समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित किया। सरकारी योजनाओं को समयबद्ध रूप से लाभार्थियों तक पहुंचाने, पीएम-केंद्रित और सीएम योजनाओं की प्रगति सुधारने पर भी जोर दिया गया।

कुशीनगर एयरपोर्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने रात्रिकालीन लैंडिंग की सभी तैयारियां शीघ्र पूर्ण कराने को कहा, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का मार्ग प्रशस्त होगा। किसान सम्मान निधि के लंबित मामलों, सीएम आवास योजना, जलापूर्ति, चौपाल आयोजन, अवैध कब्जों, ग्राम पंचायत स्तर के कार्यों, SHG समूह, लखपति दीदी, पाइपलाइन मरम्मत जैसी प्रमुख समस्याओं पर विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि तालाब, पोखरे, खलिहान व बंजर भूमि पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने रात्रिकालीन लैंडिंग संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर शासन को भेजे जाने की जानकारी दी तथा विकास परियोजनाओं व एसआईआर की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की।

अयोध्या धाम श्रीराम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में जिले के सनातनी हुए रवाना

पडरौना (कुशीनगर) । 25 नवंबर को अयोध्या धाम भगवान श्रीराम मंदिर पर प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वज फहराया जाएगा । जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से साधु संतों और समाज के निचले वर्ग के लोगों को निमंत्रण मिला है । ध्वजारोहण समारोह में पडरौना के विभिन्न गांवों से अयोध्या धाम जाने वाले साधु संतों व समाज के निचले वर्ग के लोगों को बसों और अन्य गाड़ियों से भारी संख्या में रवाना हुए । इस अवसर पर जिला प्रचारक अभय, विभाग सह कार्यवाह रवि कृति, जिलासंघ चालक रामसिंहार, धर्म जागरण प्रमुख कृष्ण कुमार पांडे, दीनानाथ, डॉ धनंजय मिश्र, प्रदीप गोयल, विशाल जायसवाल, अधिवक्ता अनूप, नीरज गोयल, विश्व हिन्दूपरिषद जिलाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी, जिला कोषाध्यक्ष पारसनाथ, जिला सहमंत्री संजय शाही, जिला बजरंग दल संयोजक अक्षय, अधिवक्ता अनिल ठाकुर, रवि सिंह, धनंजय सिंह, सनत कुमार पांडे, संतोष यादव आदि लोग मौजूद रहे।

भटनी रेलवे स्टेशन पर महिला शराब तस्कर गिरफ्तार, 30 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद

भटनी देवरिया।

राजकीय रेलवे पुलिस गोरखपुर के निर्देश पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जीआरपी थाना भटनी की टीम ने एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने उसके कब्जे से 30 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 3,600 रुपये बताई जा रही है।उच्चाधिकारियों अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे मोदक राजेश डी, पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे लखनऊ श्रीमती सुधा सिंह तथा पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र के निर्देशन में चल रहे अभियान के दौरान पुलिस उपाधीक्षक रेलवे बलिया सविरत्न गौतम के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। जीआरपी भटनी की टीम ने रेलवे स्टेशन भटनी के प्लेटफॉर्म संख्या 04 के पश्चिमी छोर से अभियुक्ता पूजा उर्फ रेखा, पत्नी मुन्नी साहनी, निवासी मरुई वार्ड नम्बर 09 बनचर, थाना पातेपुर, जिला वैशाली बिहार उम्र लगभग 42 वर्ष को गिरफ्तार किया। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि वह उत्तर प्रदेश से शराब लाकर बिहार में दोगुने दामों पर बेचती है। आज भी वह इसी मकसद से बिहार जा रही थी। बरामद शराब में 30 अदद ऑफिसर च्वाइस 180 द्रव्य प्रत्येक, कुल 5.4 लीटर शामिल है। इस संबंध में थाना जीआरपी भटनी में मु.अ.सं. 44/2025, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्ता के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में कांस्टेबल उमेश यादव, प्रमेश यादव,महिला कांस्टेबल ज्योति पाण्डेय रहे।

निक्की हत्याकांड : पुलिस ने चार्जशीट की दाखिल

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित सिरसा गांव में चर्चित विवाहित निक्की भाटी की जलाकर हत्या के मामले में कासना कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने मामले में आरोपी पति विपिन, जेठ रोहित, ससुर सत्यवीर और सास दया को आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों ने अपराधिक षड्यंत्र के तहत निक्की भाटी की हत्या को अंजाम दिया दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ व दिनेश कुमार कल्सन ने बताया कि पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कराने के साथ सजा दिलाने के लिए मजबूती से कोर्ट में पक्ष रखेंगे। पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की उसके मुताबिक दया और विपिन ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। आरोपी दोनों बहनों के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने से नाखुश थे। वीडियो बनाने से टोकने पर नहीं रुकने के कारण आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। दादरी कोतवाली क्षेत्र के रूपवास गांव निक्की भाटी की सिरसा गांव स्थित ससुराल आग से जलाकर मारने का आरोप है।

दिल्ली में छात्र आत्महत्या मामले में तीन और शिक्षकों पर पुलिस का शिकंजा, अभिभावकों का प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर 16 वर्षीय एक छात्र की आत्महत्या के मामले में तीन और शिक्षकों को पूछताछ के लिए बुलाया। रविवार को दो अन्य शिक्षकों से पूछताछ की गई, जबकि जांच के तहत कुछ छात्रों से भी पूछताछ की गई। इससे पहले, मध्य दिल्ली स्थित इस स्कूल ने अपने चार शिक्षकों को निलंबित कर दिया था। इस बीच, माता-पिता ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि स्कूल के शिक्षकों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण उनका बेटा गंभीर मानसिक तनाव में था। एएनआई से बात करते हुए मृतक के पिता ने कहा, मेरा बेटा बहुत होशियार था। उसने कई मेडल और सर्टिफिकेट जीते थे। और पिछली बार जब मैंने उससे बात की थी, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वह ऐसा कदम उठाएगा। मेरा बेटा शिकायत करता रहता था कि शिक्षक उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। इस समय, कई छात्र और अभिभावक भी मेरे बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बेटे को न्याय मिले। पीड़ित की मां ने बताया, मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए और इस मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसने मुझे कई बार बताया कि शिक्षक उसे बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और बच्चे को ऐसा कुछ न सहना पड़े। 21 नवंबर को, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशिष सूद ने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी के एक प्रतिष्ठित स्कूल के एक छात्र की आत्महत्या के मामले में एक जांच समिति गठित की है। सूद ने कहा कि स्कूलों ने भी इस मामले में कार्रवाई की है।

उन्होंने बताया कि वह स्कूलों को पत्र लिखकर पूछेंगे कि क्या वे सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी भलाई पर नजर रख रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा, हमने एक जांच समिति गठित की है और स्कूल ने कार्रवाई भी की है। मैं इसे न केवल शिक्षा मंत्री के रूप में, बल्कि एक चिंतित अभिभावक के रूप में भी देख रहा हूं। जल्द ही, मैं स्कूल को पत्र लिखकर पूछूंगा कि क्या वे सीबीएसई दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण की निगरानी कर रहे हैं। राज्य सरकार सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। हम अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर बेहद चिंतित हैं। बता दें, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले दसवीं कक्षा के एक छात्र ने एक नोट छोड़ा है, जिसमें उसने अपने स्कूल के शिक्षकों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस द्वारा 18 नवंबर को दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, छात्र ने अपने माता-पिता से शिक्षकों के व्यवहार के बारे में बार-बार शिकायत की थी, लेकिन हस्तक्षेप की उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया गया।

राम मंदिर एटीएस-एनएसजी कमांडोज के घेरे में पीएम मोदी आज धर्मध्वजा फहराएंगे

अयोध्या।

अयोध्या में 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक और स्वर्णिम क्षण लेकर आएगा. इस दिन राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल होंगे. उनके स्वागत के लिए 501 वटुक ब्राह्मण स्वस्तिवाचन करेंगे, जबकि संत-महंत शंखनाद और घंट-घड़ियाल की ध्वनि से वातावरण को भक्तिमय बनाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी पहले महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर वहां से साकेत महाविद्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे. महाविद्यालय से राम जन्मभूमि तक के मार्ग पर 12 स्वागत मंच बनाए गए हैं, जहां पुष्प वर्षा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उनका अभिनंदन किया जाएगा. अयोध्या नगरी को दीपों और रोशनियों से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. हर घर पर दीपमाला जलेगी, तिरंगा और भगवा ध्वज लहराएंगे. मार्ग में भजन, ब्रज लोकधुन, शहनाई, बांसुरी और सितार जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर प्रस्तुति स्वागत को भव्य बनाएगी. साधु-संत, स्थानीय नागरिक, स्कूलों के विद्यार्थी और महिलाएँ कतारबद्ध होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगी.

हर घर पर लगाया जाएगा तिरंगा व भगवा ध्वज

विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है. अयोध्या वासी अपने घरों और दुकानों पर लाइटिंग सजाएंगे, हर घर पर तिरंगा व भगवा ध्वज लगाया जाएगा. जगह-जगह स्वस्तिवाचन का आयोजन होगा और अवधी-संस्कृत के कलाकार प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे. संजू सिंह के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी साकेत महाविद्यालय के हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से सड़क मार्ग से राम मंदिर जाएंगे.

साकेत महाविद्यालय से गेट नंबर 11 तक मार्ग को विशेष रूप से सजाया जा रहा है. रास्ते में अयोध्यावासी, साधु-संत, महिलाएँ और स्कूलों के छात्र कतारबद्ध होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे, ताकि इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाया जा सके.

भगवा और तिरंगा से सजेगा घर, पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ेगा जनसैलाब

शहर में दीपावली जैसा माहौल

पंकज गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से लोग बेहद उत्साहित हैं. यह अयोध्या के लिए गौरव का पल है.एक बार फिर शहर में दीपावली जैसा माहौल बनेगा, पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा. शहजादी बाल संत दिवाकर आचार्य ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में वैदिक विद्वान और साधु-संत भी शामिल होंगे. पुष्प वर्षा के साथ उनका अभिनंदन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह वह ऐतिहासिक समय होगा, जब प्रधानमंत्री 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मंदिर पूर्णता का संदेश विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे जो अयोध्या के लिए अत्यंत गर्व की बात है.

नहीं रहे बॉलीवुड के ही-मैन

पंचतत्व में विलीन हुए धर्मेंद्र, विले पार्ले श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार

मुंबई। मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार को मुंबई में उनके घर पर 89 साल की उम्र में निधन हो गया। एक्टर को इस महीने की शुरुआत में सांस की दिक्कतों के चलते ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अपने पीछे छह दशकों से ज्यादा की शानदार सिनेमाई विरासत छोड़ गए हैं। उनकी आखिरी ऑन-स्क्रीन मौजूदगी इक्कीस में होगी, जो 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी। धर्मेंद्र के परिवार में उनकी पत्नियां, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, और छह बच्चे हैं - एक्टर सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, और अहाना देओल, साथ ही अजीता और विजेता। इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक माने जाने वाले धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। गंभीर और हास्य भूमिकाओं में समान रूप से अपनी प्रतिभा साबित करने वाले अभिनेता को 2012 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। छह दशकों के करियर में उन्होंने शोले, यादों की बारात, मेरा गाँव मेरा देश, प्रतिज्ञा, चुपके चुपके, नौकर बीवी का, फूल और पत्थर, सत्यकाम, आई मिलन की बेला, दिल ने फिर याद किया, आए दिन बहार के, आँखें, आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, जुगनू, चरस, धरम वीर, आजाद, गजब, लोहा, हुकूमत और अपने सहित कई हिट फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र के शानदार रोल्स और उनके बेटों बॉबी और सनी देओल की वजह से देओल परिवार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखी है, जिन्होंने एक जमाने को पहचान दी। उनकी पत्नी हेमा मालिनी को बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल भी कहा जाता है। इसके अलावा, उनकी बेटियों ईशा और अहाना देओल ने भी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। धर्मेंद्र, जिन्हें प्यार से बॉलीवुड का ही-मैन कहा जाता है, अपने पीछे एक ऐसी फ़िल्मोग्राफ़ी छोड़ गए हैं जिसने भारतीय सिनेमा के शिखर पर असर डाला। उन्होंने छह दशकों में 300 से ज्यादा फ़िल्मों में जबरदस्त एक्शन हीरो से लेकर सेंसिटिव रोमांटिक लीड तक सब कुछ निभाया। 1966 की फ़िल्म फूल और पत्थर में शक्ति सिंह के रोल से लेकर, कल्ट-क्लासिक फ़िल्म शोले में वीरू के मशहूर रोल से लेकर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा चुपके चुपके तक, उनकी एक्टिंग में दम और चार्म दोनों थे। उनकी ऑन-स्क्रीन प्रेज़ेंस और गहरी आवाज़ ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया। स्क्रीन के अलावा, धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे जाने-माने परिवारों में से एक के लीडर थे। उनके छह बच्चे थे, जिनमें एक्टर सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल शामिल हैं। उन्होंने पहले प्रकाश कौर से और फिर एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की। उनकी विरासत को देओल परिवार आज भी संभाले हुए है, जिसमें हर पीढ़ी भारतीय सिनेमा में कुछ अनोखा योगदान दे रही है।

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा- भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत

राबड़ी देवी ने जज को लेकर उठाए सवाल, अब दिल्ली कोर्ट में दायर की नई याचिका

नई दिल्ली। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर की है। उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने वाले न्यायाधीश विशाल गोगने से चार मामलों को स्थानांतरित करने के लिए की मांग को लेकर याचिका दायर की है। राबड़ी देवी ने न्यायाधीश पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पूर्व नियोजित तरीके से मुकदमा चला रहे हैं। याचिका में कहा गया कि न्यायाधीश गोगने अभियोजन पक्ष के प्रति अनुचित रूप से पक्षपाती हैं। राबड़ी देवी ने आवेदन में न्यायाधीश गोगने के समक्ष लंबित आइआरसीटीसी घोटाला मामला, नौकरी के बदले भूमि का मामला और उनसे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग की है। 13 अक्टूबर को न्यायाधीश गोगने ने आइआरसीटीसी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कई अन्य के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए थे।

जस्टिस सूर्यकांत ने ली नए सीजेआई पद की शपथ, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कई वर्तमान न्यायाधीशों की उपस्थिति में उन्हें शपथ दिलाई। इस समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई शीर्ष गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ।

उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएँ। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली, जिसके साथ ही भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में उनके लगभग 15 महीने के कार्यकाल की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कई वर्तमान न्यायाधीशों की उपस्थिति में उन्हें शपथ दिलाई। इस समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई शीर्ष गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। शपथ लेने के तुरंत बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के पैर छुए, जिससे इस ऐतिहासिक अवसर में एक भावुक और पारंपरिक क्षण जुड़ गया। इस कार्यक्रम में वैश्विक न्यायपालिका ने भी भाग लिया। शपथ समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरीशस, नेपाल और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए।

इनमें भूटान के मुख्य न्यायाधीश ल्योनपो नोरबू शेरिंग, केन्या की मुख्य न्यायाधीश मार्था कूमे, मलेशिया की न्यायमूर्ति तन श्री दातुक नलिनी पथमनाथन, मॉरीशस की मुख्य न्यायाधीश बीबी रेहाना मुंगली-गुलबुल, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश पी. पद्मन सुरेसेना, तथा उनके साथ आए न्यायाधीश और अधिकारी शामिल थे।

उत्तराखंड के टिहरी में बस के खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी

टिहरी। उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्रनगर क्षेत्र में कुंजापुरी-हिंडोलाखाल के पास सोमवार को लगभग 28 यात्रियों को ले जा रही एक बस के 70 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान जारी है। राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) के अधिकारियों के अनुसार, जिला नियंत्रण कक्ष ने सोमवार दोपहर एसडीआरएफ वाहिनी नियंत्रण कक्ष को दुर्घटना की सूचना दी, जिसमें बताया गया कि वाहन नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र में सड़क से फिसल गया था। शुरुआत में बस में 30 से 35 लोगों के सवार होने का अनुमान लगाया गया था। अलर्ट पर कार्रवाई करते हुए, एसडीआरएफ ने पोस्ट ढालवाला, पोस्ट कोटी कॉलोनी और एसडीआरएफ कोर मुख्यालय से पांच टीमों को घटनास्थल पर तैनात किया। एसडीआरएफ अधिकारियों ने घटनास्थल पर पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है। अन्य सभी घायल यात्रियों को खाई से निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बस में सवार यात्री कथित तौर पर राज्य के बाहर के थे। आगे की जानकारी का इंतजार है और जैसे ही यह प्राप्त होगी, इसकी प्रति अपडेट कर दी जाएगी।

दिल्ली-सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर मिली दो नई ट्रेनों की सौगात, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी

बड़ौत (बागपत)। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को दोपहर 1.30 बजे बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही फूलों से लदी दोनों ट्रेनें बड़ौत रेलवे स्टेशन से दिल्ली और शामली के लिए रवाना हो गईं। दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग पर यह दैनिक यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा रेलमंत्री और केंद्रीय मंत्री जयन्त चौधरी ने चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी बड़ौत के चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल पहुंचे और स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद दोनों बड़ौत रेलवे पर पहुंचे और दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक ट्रेन दिल्ली और दूसरी ट्रेन शामली के लिए रवाना हुई। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि दोनों ट्रेनों के संचालन से गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली के लोगों को फायदा होगा। दोनों ही कार्यक्रमों में मंत्रियों का स्वागत किया गया। बता दें कि बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों को हरी झंडी के इंतजार में सुबह ही फूलों से लदकर स्टेशन पर पहुंच गई थीं। बस शुभारंभ का इंतजार था। दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग पर यह दैनिक यात्रियों के लिए बड़ी सौगात होगी।

यह है यात्रियों की प्रमुख मांग..........

- -ट्रेनों का नियमित और समय पर संचालन सुनिश्चित करना।
- -नई पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत हो, जिससे आवागमन बेहतर हो सके।
- -रेल पुलिस द्वारा यात्रियों में शराब पीने और अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई।
- -रेलमार्ग के रख-रखाव और तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया

अयोध्या।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सोमवार को अयोध्या पहुंचे, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराकर ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ करेंगे।

उनका एयरपोर्ट से साकेत महाविद्यालय तक हेलीकॉप्टर से पहुंचना प्रस्तावित है। साकेत महाविद्यालय से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक भव्य रोड शो भी आयोजित होगा। रोड शो के एक किमी लंबे रामपथ को आठ जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पारंपरिक तरीके से थाली, आरती, फूल-माला और नमस्कार मुद्रा के साथ पीएम की अगवानी करेंगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए अलग-अलग समाज और समूहों की महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी है।

व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद कर दिया गया

ध्वजारोहण समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद कर दिया गया है। पुलिसकर्मी जगह-जगह पर तैनात हैं। एडीजी जोन सुजीत पांडेय ने ध्वजारोहण कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस लाइन में उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को कार्य-व्यवहार और कर्तव्यों का बोध कराया। बताया कि अपनी तैनाती स्थल पर मुस्तैदी से डटे रहें। आगंतुकों से उत्तम व्यवहार करते हुए उन्हें जारी गाइडलाइन से अवगत कराएं। अराजकतत्वों पर विशेष नजर रखें। उन्होंने राम मंदिर परिसर, साकेत महाविद्यालय व अन्य कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराकर ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ करेंगे। उनका एयरपोर्ट से साकेत महाविद्यालय तक हेलीकॉप्टर से पहुंचना प्रस्तावित है। साकेत महाविद्यालय से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक भव्य रोड शो भी आयोजित होगा।

एसआईआर पर शोर मचाने वाले दलों के मन में चोर : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि ''एसआईआर को लेकर शोर मचाने वाले दलों के मन में चोर है। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सह प्रभारी रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स पर पोस्ट किया,''मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर शोर मचाने वाले दलों के 'मन में चोर है। बिहार ने साबित कर दिया है कि उनका पक्ष कमजोर है। बिहार के हाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने प्रचंड जीत हासिल की और 'इंडिया गठबंधन के दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने एसआईआर को लेकर लगातार सरकार और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है।

मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझने की भूल न करें, दिल्ली आतंकी ब्लास्ट पर बोले ओवैसी

नई दिल्ली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक भाषण के दौरान दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की खुलकर निंदा की, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने मुसलमानों को गाली देने और उनसे वफादारी का प्रमाणपत्र मांगने वालों को भी संदेश देते हुए कहा कि हमने कभी अपने देश से नफरत नहीं की। उल्लेखनीय है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट में शामिल मुख्य चार आरोपी, जिसमें 15 लोग मारे गए थे, अल फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टर थे, जिनमें डॉ. उमर नबी भी शामिल थे, जो विस्फोटक से लदी हुंडई आई20 कार चला रहा था। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की निंदा करते हैं जो किसी शैक्षणिक संस्थान में बैठकर बम बनाने की साजिश रचता है... (दिल्ली विस्फोट में) हिंदुओं और मुसलमानों समेत 14 लोग मारे गए। हमें ऐसे सभी लोगों की खुलकर निंदा करनी चाहिए। देश के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं।

अगर ऐसा किया जाता है, तो हम इन क्रूर लोगों को जो चाहे करने की खुली छूट दे रहे होंगे। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक दुनिया रहेगी, भारतीय मुसलमान देश में सम्मानित नागरिक के रूप में रहेंगे। उन्होंने कहा कि (दिल्ली विस्फोट में) हिंदू और मुसलमान समेत 14 लोग मारे गए। हमें ऐसे सभी लोगों की खुलकर निंदा करनी चाहिए। देश के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। अगर ऐसा किया जाता है, तो हम इन क्रूर लोगों को मनमानी करने की खुली छूट दे रहे होंगे।